ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Ranjinder Nagar, New Delhi - 110060
E-mail : alstonetextiles@gmail.com, Website : alstonetextiles.in
CIN : L65929DL1985PLC021037, Tel. : 011-41232222, Mob. : +91-9643924382

**Date: 07-09-2023**

**To,**
**BSE Limited**
**P.J. Towers Dalal Street**
**Mumbai - 400001**

**Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of the Annual General Meeting of the Company, Book Closure, Information on E-Voting and other related information**

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement regarding Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 29th September 2023, Through video conferencing / other audio video visual means, book closure, information on E-Voting And other related information published in the following newspapers.

| Newspaper(s) | Language | Date of Publication |
|---|---|---|
| Hindi Daily Open Search | Hindi | **7th September, 2023.** |
| English Daily Open Search | English | |

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements published.

We request you to kindly take the above in your records.

Kindly take the same into record.

**For Alstone Textiles (India) Limited**
DEEPAK KUMAR BHOJAK

Digitally signed by DEEPAK KUMAR BHOJAK
DN: cn=DEEPAK KUMAR BHOJAK, c=IN, st=Rajasthan, o=Personal, serialNumber=882B470AC80D6F7867789D3B4D39C87702A35A4E4E4EAB729C698CBA94BE84A7
Date: 2023.09.07 13:43:49 +05'30'

**Deepak Kumar Bhojak**
**(Managing Director)**
**DIN: 06933359**

**Encl- a/a**

सूर्योदय - 05:25
सूर्यास्त - 07 : 15

अधिकतम तापमान 40.0°
न्यूनतम तापमान 31.1°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 09 अंक : 253 नई दिल्ली, गुरूवार 07 सितम्बर-2023 | नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित | ₹ मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

# देश में नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए सब्सिडी

**नई दिल्ली.एजेंसी**

सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के के लिए बड़ी बैटरियों के विनिर्माण पर 3760 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वर्ष 2030 तक देश की कुल ऊर्जा जरूरतों में कम से कम 50 प्रतिशत की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

श्री ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय पवन ऊर्जा का उत्पादन 40 जीगावाट (40 हजार मेगावाट) और सौर ऊर्जा का उत्पादन 71 जीगावाट (71000 मेगावाट) तक है। इन दोनों स्रोतों का देश के कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 15 प्रतिशत है। यदि पनबिजली को जोड़ दिया जाए तो देश में करीब 25 प्रतिशत बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवीकरणीय स्रोतों से बनायी जा रही

बिजली के भंडारण की व्यवस्था में कमी को दूर करने के लिए 4000 मेगावाट प्रतिघंटा से अधिक क्षमता वाली बैटरियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 3760 करोड़ रुपये की वाइबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) का प्रावधान किया है। सरकार की ओर से वीजीएफ का प्रावधान ऐसी परियोजना के लिए किया जाता है जो महत्वपूर्ण होती है पर शुरू में किसी निवेशक के लिए बिना सरकारी सहायता के व्यावहारिक नहीं दिखती । इसके तहत हर यूनिट को पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत तक की सहायता मिलेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि बड़ी बैटरी के विनिर्माण पर वीजीएफ की यह सहायता वर्ष 2030-31 तक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन एवं भंडारण करने वाली इकाइयों को 85 प्रतिशत ऊर्जा विद्युत वितरण कंपनियों को देनी होगी। उसके बाद ही वे बची ऊर्जा को किसी अन्य को दे सकेंगे। इससे उत्पादन एवं खपत दोनों बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोत्साहन से नवीकरणीय ऊर्जा की स्टोरेज बैटरी के विनिर्माण के क्षेत्र में 9500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और जीवाश्म आधारित ईंधन पर निर्भरता कम करने में बहुत कारगर साबित होगी।

## हिमाचल-उत्तराखंड को 1664 करोड़ का आवंटन

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को औद्योगिक विकास योजना के तहत 1664 करोड़ रुपए की मदद करने का निर्णय लिया है ताकि दोनों पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक विकास को गति मिले और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल में पलायन की समस्या है। रोजगार के अवसर नहीं होने से वहां लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं इसलिए वहां औद्योगिक विकास आवश्यक है। इसी जरूरत को देखते हुए सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक दिसम्बर 2002 को विशेष औद्योगिक पैकेज पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड तथा जम्मू- कश्मीर को दिया था जिसके कारण वहां बड़े स्तर उद्योग खुले, निवेश हुआ और लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के औद्योगिक विकास की गति को जारी रखते हुए 2014 में जब मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया और फिर 2017 में औद्योगिक विकास योजना के तहत इन राज्यों में नयी यूनिट लगाने पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की। यह सब्सिडी संयंत्र लगाने के लिए दी गई।

# गणेश चतुर्थी से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद

18 सितंबर को विशेष सत्र के पहले दिन का कामकाज पुरानी बिल्डिंग में होगा

**नई दिल्ली (एजेंसी)**

केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहला दिन यानी 18 सितंबर पुराने संसद भवन में कामकाज का आखिरी दिन होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का इनॉगरेशन किया था। इसमें कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी इमारत को 'म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी' में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नया संसद भवन बनाया गया है।

973 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग को 29 महीने में तैयार किया गया है। नई संसद के इनॉगरेशन पर तमिलनाडु से आए संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा था। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया था। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद थे। इनॉगरेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में पीएम ने आजादी के 75वें साल पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट किया था। मौजूदा संसद भवन को 95 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई गई है। 64 हजार 500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं, इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और VIPs के लिए अलग एंट्री है। नया भवन पुराने भवन से 17 हजार वर्ग मीटर बड़ा है।

नए संसद भवन पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसकी डिजाइन HCP डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है।

**19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का इनॉगरेशन किया था। इसमें कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी इमारत को 'म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी' में बदल दिया जाएगा।**

## एक नज़र

### मुर्मु ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी

**नई दिल्ली.एजेंसी** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है , जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले अपने सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का एक सुअवसर भी है। यह त्योहार लोगों के बीच प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़कर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग दिखाया है। श्री श्रीकृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से 'निष्काम कर्म' का संदेश दिया।

## भारत दाल, प्याज की बिक्री करेगा एचसीसीएफ : चौबे

**नई दिल्ली.एजेंसी**

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को

कहा कि सरकार को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एचसीसीएफ) के माध्यम से प्याज 25 रुपये तथा दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगी। श्री चौबे ने आज यहां से हौज खास स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय से 75 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल वैनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर भारत दाल और प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। यह वैन दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलेंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैन का संचालन एचसीएफ द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले में टमाटर की कीमत आसमान छू रही थी, तो केंद्र सरकार ने टमाटर की बिक्री किफायती दरों पर की थी, जिसकी सफलता के बाद सरकार ने अब इस वैन को चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ तथा नेफेड क्रमश 500-500 वैन चलाएंगे। इससे उपभोक्ताओं और किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इन वैनों में मिलेट आदि की भी उपलब्धता होगी। साथ ही भविष्य में अन्य खाद्य सामग्रियां भी किफायती दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वैन के माध्यम से मौजूदा समय मे प्याज 25 रुपये तथा दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा। इस मौके पर एचसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह, उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह, एनसीएफ की प्रबंध निदेशक एनसी जोसेफ चंद्रा उपस्थित रहे।

## आपदा से जूझ रहे हिमाचल को ओडिशा सरकार की सहायता

### प्रदेश में राहत के लिए दिए पांच करोड़

**शिमला.ओपन सर्च**

बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को समर्थन देते हुए, ओडिशा सरकार ने बुधवार को पहाड़ी राज्य में प्रभावित आबादी के राहत और पुनर्वास के लिए पांच करोड़ रुपये का दान दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में उदार दान से राज्य के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता करने में मदद मिलेगी। बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों ने भी हिमाचल प्रदेश को 51 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की है। सीएम सुक्खू ने आम जनता से भी आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भर से सामूहिक प्रयास और योगदान निश्चित रूप

से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को व्यापक समर्थन और सहायता सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए राज्य द्वारा स्थापित आपदा राहत कोष (राज्य आपदा राहत कोष) में 168 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। वर्तमान मानसून ने हिमाचल प्रदेश में सड़कों, बुनियादी ढांचे, जलापूर्ति योजनाओं, इमारतों, अन्य निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 24 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 5 सितंबर तक राज्य को अनुमानित नुकसान 8,675 करोड़ रुपये आंका गया है। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 261 और सड़क दुर्घटनाओं में 147 लोगों सहित कुल 408 लोगों की मौत हो गई है।

## मणिपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने ईजीआई के सदस्यों दी राहत

**नई दिल्ली.एजेंसी**

उच्चतम न्यायालय ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के सदस्यों को मणिपुर में हिंसक जातीय झड़पों पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के लिए उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उन प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग वाली ईजीआई की ओर से दायर याचिका पर मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने ईजीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने पर मामले की सुनवाई शुरू की। श्री दीवान ने पीठ के समक्ष कहा कि सदस्यों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तत्काल सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा, अदालत के समक्ष चार रिट याचिकाकर्ता हैं। हम उन में गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाईयों से सुरक्षा

की मांग कर रहे हैं। श्री दीवान ने कहा कि गिल्ड के चार सदस्यों ने मणिपुर के कुछ लोगों का साक्षात्कार लिया और फिर एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट तैयार की। तथ्यान्वेषी रिपोर्ट दो सितंबर को जारी की गई। इसके बाद उनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई। गिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध को मीडिया रिपोर्टों के लिए हानिकारक बताया था। कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा एकतरफा रिपोर्टिंग की आलोचना की थी और दावा किया था कि ऐसे संकेत थे कि राज्य नेतृत्व 'पक्षपातपूर्ण' हो गया था।

## कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बनाई कई समितियां

**नई दिल्ली.एजेंसी**

कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमेटी, समन्वय समिति, घोषणा पत्र समिति सहित कई समितियों का गठन किया है।

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन समितियों के लिए सभी नामों को संस्तुति दी है। कोर कमेटी का का प्रमुख राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया है जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यख गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्र जीत मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी तथा गोविंद राम मेघवाल को इसका सदस्य बनाया गया है। समन्वय समिति में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्रसिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्र जीत मालवीय, मोहन प्रकाश, गिरजा व्यास, नरायन सिंह, बी डी कल्ला, चंद्रभान, रघुवीर सिंह मीणा, नमो नाराण मीणा, रघु शर्मा, हेमराम चौधरी, प्रसादीलाल मीणा, उदयलाल अंजना, भजन लाल जाटव, टीकाराम जुली, भंवर सिंह भाटी, ताराचंद भगोरा, शांति धारीवाल, गुरमीत सिंह कुन्नर, मंजू देवी मेघवाल, महेंद्र चौधरी तथा दिनेश खोडानिया को सदस्य बनाया गया है। प्रचार समिति का जिम्मा गोविंद राम मेघवाल को दिया गया है जबकि उपाध्यक्ष अशोक चांदना, संयोजक राज कुमार शर्मा और सह संयोजक दानिश अबरार औरचेतन दूढी को बनया गया है।

समिति में प्रताप सिंह खचारियावास, रामल जाट, कृष्णा पूनिया, गणेश गोर्गा, रामलाल मीणा, वैभव गहलोत, महेंद्र गहलोत, घनश्याम मेहर, गजेंद्र सिंह संखला, कृष्णलाल जेडिया, जगदीश श्रीमाली, राखी गौतम, हेमसिंह शेखावत, अभिषेक चौधरी, यशवीर शूरा तथा नीतू कंवर भाटी को बनाया गया है। चुनाव घोषणा पत्र का अध्यक्ष सीपी जोशी और उपाध्यक्ष नीरज डांगी को बनया गया है जबकि संयोजक गौरव बल्लभ, सह संयोजक टीकाराम मीणा और पुखराज पराशर को बनाया गया है।

# हरियाणा में पिछले 10 सालों के मुकाबले करवाए दोगुने विकास कार्य : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

### मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर थुराना में लगभग 14.50 करोड रुपए की लागत से पेयजल पाईप डालने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की

**ओपन सर्च. संवाददाता**

**हांसी।** मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम से अब तक 19 हजार समस्याएं आई हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इनमें से 2500 पूरी की जा चुकी हैं और 13 हजार की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। जन संवाद में आने वाली सभी समस्याओं का रिकॉर्ड रख उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को तीन दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम के तहत जिला हिसार के हांसी हलके के गांव थुराना में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसी भी कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्यों के लिए जिला परिषदें और पंचायतें अपने स्तर पर कार्य करें। कुछ फंड राज्य सरकार

से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और पिछले दस सालों में किए गये कार्यों के मुकाबले वर्तमान सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में दोगुने विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर थुराना में लगभग 14.50 करोड रुपए की लागत से पेयजल पाईप डालने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा तीन सड़कों का निर्माण एंव कच्ची फिरनी को पक्की करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने 15 गलियों को पक्का करने और शिवधाम योजना के तहत तीन शमशान घाट की चारदिवारी, पेयजल, रास्ते एवं कब्रिस्तान का रास्ता पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने अनुसूचित जाति की बस्ती में बरसाती पानी की निकासी एवं भाटोल रोड पर खेतों में जलभराव की निकासी करने के कार्य को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने गांव के बिजली घर में 4 एमबीए से बढाकर 10 एमबीए का ट्रांसफार्मर लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने गांव के खरीद केन्द्र को सब यार्ड बनाने की मंजूरी प्रदान की। लगभग 12 एकड़ में बनने वाले इस सब यार्ड पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की ओर से गांव के खेल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक से लेकर बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जांएगी। मुख्यमंत्री ने गांव थुराना के 9 पात्र परिवारों को पेंशन योजना के प्रमाण सौंपें।

आयुष्मान योजना का जिक्र करते उन्होंने बताया कि गांव के 70 लोगों ने इस योजना के तहत 22.74 लाख रुपए का लाभ उठाया है, जिनमें से 5 लोगों ने एक लाख रुपए से अधिक का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि गांव के 26 युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया तथा 92 युवाओं को ऋण देने का कार्य पाईप लाईन में है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को गांव के स्कूल में वोकेशनल कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए।

## एक नज़र

### अर्जुन अवाड्री योगेश कथूनिया ने ग्रिवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी के साथ की ग्रहमंत्री अनिल विज से शिष्टाचार भेंट

**बहादुरगढ़ ओपन सर्च।** पेरा एथलिट्स डिस्कस थ्रो में अर्जुन अवाड्री योगेश कथूनिया ने प्रदेश के ग्रहमंत्री अनिल विज से उनके अम्बाला स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की। उनके साथ झज्जर ग्रिवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी मौजूद थे। प्रदेश के ग्रहमंत्री ने योगेश को बधाई देते हुए कहा की प्रदेश व केंद्र सरकार ने देश में खेलो को बढ़ाया देने के लिए साकारात्मक कदम उठाये है। इसी की बदौलत आज देश ने खेलो के क्षेत्र में तरक्की की है।

सरकार ने खेलो को बढ़ावा देकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के ग्रहमंत्री ने योगेश कथूरिया को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का विश्वास दिलाया। वही योगेश कथूनिया ने जहाँ प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की खेल नीति की सराहना की वही आने वाले समय में डिस्कस थ्रो में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया।

### पार्किंग में बच्चे को दिया जन्म, महिला की अस्पताल में मौत, बिहार की रहने वाली थी

**हलवारा (एजेंसी)** पंजाब के जगरांव के समीप गुरुद्वारा श्री नानकसर कलेरां साहिब की वाहन पार्किंग में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला काफी देर तक वहीं तड़पती रही लेकिन मेडिकल सुविधा न मिलने के चलते वो बेहोश हो गई। नानकसर संप्रदाय के मौजूदा मुखी संत बाबा लक्खा सिंह ने तुरंत पुलिस और जगरांव सिविल अस्पताल को सूचित किया।

मगर मदद पहुंचने से पहले ही महिला ने वाहन पार्किंग में बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद जगरांव के थाना सिटी में तैनात एएसआई तरसेम सिंह मौके पर पहुंचे। महिला की हालत खराब होती देख संत बाबा लक्खा सिंह ने खुद ही एंबुलेंस का इंतजाम किया और महिला व नवजात को सिविल अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक महिला और बच्चे को अलग करने के लिए नाड़ा भी समय रहते नहीं काटा गया और दोनों को वैसे ही उठाकर कर अस्पताल ले गए।

### पत्नी को भगा ले गया युवक, पति लेने गया तो पिस्तौल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी; आरोपी गिरफ्तार

**पानीपत (एजेंसी)** पानीपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अन्य युवक की पत्नी को भगा ले गया। वहीं, जब उसका पति उसे वापसे लेने पहुंचा था तो हथियार के दम पर उसे भगा दिया। दरअसल, विजय नगर से एक युवक महिला को भगा ले गया। महिला का पति जब उसे लेने गया तो आरोपित ने उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से पीड़ित डरा हुआ है।

थाना तहसील कैंप क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि विजय नगर का रहने वाला है। उसकी शादी करीब आठ साल पहले सोनिया नाम की महिला से हुई थी। वह एक बेटी का पिता है। उसकी पत्नी को विजय नगर का पंकज अपने पास करीब 10 दिन से रख रहा है। जब वह अपनी पत्नी को लेने उसके घर जाता है तो वह उसे कभी पिस्तौल तो कभी तलवार दिखाता है। वह एक दुनाली बंदूक भी अपने साथ रखता है।

### जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए बाजारों में उमड़े श्रद्धालु, मंदिरों में आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू

**अंबाला (एजेंसी)** जन्माष्टमी पर जिला भर में श्रीकृष्ण व राधा की मूर्तियों, झूलों व पोशाकों की धूम है। इस त्योहार को लेकर जहां उत्साह है, वहीं जिला में करीब 65 लाख रुपये के कारोबार का अनुमान है।

दो दिनों तक यह आयोजन होगा, जबकि अंबाला में यह मुख्य आयोजन 6 सितंबर को होगा। मंदिरों को जहां सजाया गया है, वहीं इसके आसपास मेले का माहौल है। कारोबारियों की मानें, तो आकर्षक झूले, पोशाक और राधा-कृष्ण की मूर्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दिन भर दुकानों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कैंट में सबसे ज्यादा भीड़ रामबाजार में रही, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाजार में जन्माष्टमी को लेकर झूलों का विशेष क्रेज देखने को मिल रहा है। यह सौ रुपये से लेकर सात हजार रुपये कीमत के मिल रहे हैं। बाजार कान्हा के श्रृंगार से सजे हैं, जबकि राधा-कृष्ण की रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, मुकुट, झूला, सिंहासन, भोग की थाली व माखन-मटकी आदि सामान लोग खरीद रहे हैं।

### चालान काटने पर पुलिस से भिड़े बाप-बेटे, सड़क पर चला ड्रामा

**सोनीपत (एजेंसी)** रेलवे रोड पर बिना हेलमेट गुजर रहे स्कूटी पर सवार होकर गुजर रहे दो भाइयों को रोकने की कोशिश की तो दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उलझ गए। इससे पहले भागने के क्रम में उन्होंने स्कूटी पर बच्चे को लेकर जा रही महिला को भी टक्कर मार कर गिरा दिया। पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ा तो पुलिस को ही धौंस दिखाने लगे। दोनों भाई काफी देर तक सड़क पर ड्रामा करते रहे।

बेटों के फोन करने पर हिमायत के लिए उनका पिता भी मौके पर पहुंच गया और अभद्रता पर उतर आया। इसके बाद आसपास के लोग भी सड़क पर एकत्रित हो गए। इससे जाम जैसी स्थिति बन गई। बाद में पुलिस तीनों बाप-बेटों को सिविल लाइन थाने में ले गई। मामले में यातायात पुलिस ने अभद्रता, लाइसेंस और हेलमेट का 11 हजार रुपये का चालान किया। सड़क पर काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तीनों बाप-बेटे ऊंची पहुंच होने की बात कहते रहे।

# सड़क हादसे में घायलों को पहले 48 घंटे मिलेगा मुफ्त इलाज, भगवंत मान सरकार

**चंडीगढ़ (एजेंसी)**

सड़क हादसे में घायल होने वालों की जान बचाने के लिए पंजाब सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब फरिश्ते स्कीम के तहत हादसे के पहले 48 घंटों में सभी पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि चाहे व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, पंजाब सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना के सभी पीड़ितों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। हादसे के पहले 48 घंटों के दौरान निजी अस्पतालों सहित पास के अस्पतालों में फ्री इलाज को यकीनी बनाया जाएगा।

मंगलवार को मगसीपा में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा करवाए एक समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को सम्मान पत्र और 2000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल लेकर आने वाले व्यक्ति से अस्पताल अधिकारी या पुलिस की तरफ से तब तक कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।

जब तक वह खुद अपनी मर्जी से चश्मदीद गवाह नहीं बनना चाहता। उन्होंने लोगों को एंबुलेंस को रास्ता देने और अपने वाहनों में हमेशा फस्ट ऐड किट रखने की भी अपील की। लीड एजेंसी के डायरेक्टर जनरल आर. वेंकटरत्नम ने कहा कि पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ट्रॉमा केयर डॉक्टरों और पैरा मेडीकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए पीजीआई के साथ समझौता करेगी। एडीजीपी अमरदीप सिंह राय ने कहा कि पंजाब सड़क सुरक्षा बल-सड़क सुरक्षा को समर्पित विशेष टीम की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके अंतर्गत नये हाई-टेक वाहन मुहैया करवाए जाएंगे और पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग वर्दी तैयार की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी और निजी सभी एंबुलेंस को ओला/उबर की तर्ज पर आपस में जोड़ा जाएगा। इससे हादसे के समय लोगों को 15 मिनट के अंदर वाहन उपलब्ध हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम राज्य मार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों की भी शिनाख्त कर रहे हैं जिससे मजबूत क्रिटीकल केयर यूनिटों की स्थापना करके लोग सरकारी स्वास्थ्य सहूलतों पर विश्वस्तरीय इलाज सुविधाओं का लाभ ले सकें।

# स्ट्रीट वेंडर्स और पथ विक्रेताओं के लिए वरदान साबित हो रही पीएम स्वनिधि योजना रू डीसी अनीश यादव

**ओपन सर्च. संवाददाता**

**करनाल।** डीसी अनीश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों व पथ-विक्रेताओं के जीवन उत्थान में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इस योजना से स्वनिधि से समृद्धि के द्वार खुले हैं और गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। इससे गरीब परिवारों के लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इस योजना का लाभ पात्रों को लाभ देने में करनाल जिला प्रदेश में अग्रणी जिलों की सूची में शामिल है। डीसी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है।

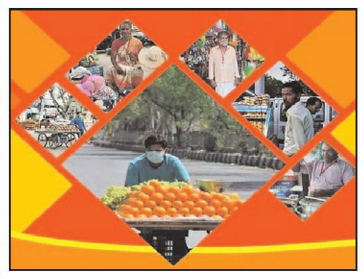

इसमें रेहड़ी व फड़ी संचालकों को 10 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। इसी में स्वनिधि से स्मृद्धि योजना है, जिसमें समय पर ऋण अदा करने वालों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की आठ प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण, वन नेशन-वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना व पीएम मातृ वंदना योजना से जोड़ा गया है, जो इनका लाभ ले सकते हैं। डीसी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी व फड़ संचालकों को उनका कार्य शुरु करवाने के लिए दस हजार रुपए ऋण मुहैया करवाया जाता है, जो 12 आसान किस्तों में चुकाना होता है। इसमें 7 प्रतिशत ब्याज केंद्र सरकार और 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार वहन करती है। इसके अलावा लाभार्थियों द्वारा डिजीटल लेन देन करने पर हर महीना 100 रुपए इनके खाते में आते हैं, यानि इनकी ब्याज राशि एक तरह से माफ हो जाती है।

# जी20 मीटिंग के मद्देनजर भारी वाहनों का 08 सितम्बर से 10 सितंबर 2023 तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित

**ओपन सर्च. संवाददाता**

**बहादुरगढ़।** राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी जी-20 मीटिंग के मध्येनजर झज्जर, बहादुरगढ़ व बादली की तरफ से दिल्ली को जाने वाले भारी वाहनों को रोककर उनके मार्ग को बदलने तथा वैकल्पिक मार्ग की तरफ मोड़ने के सम्बन्ध में एसपी डॉ अर्पित जैन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। दिल्ली में आयोजित जी 20 मीटिंग के मध्येनजर दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया गया है।

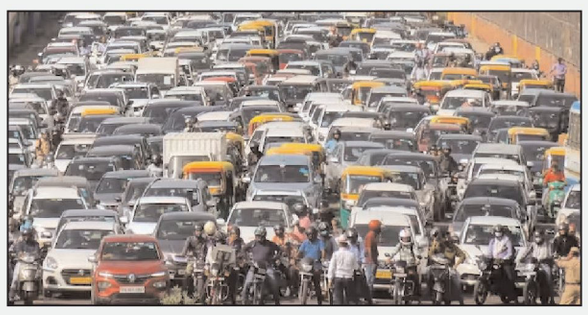

दिल्ली को जाने वाले भारी वाहनों के लिये मार्ग में परिवर्तन करके उन्हें वैकल्पिक मार्गों की तरफ मोड़ा जा रहा है। एसपी डॉ अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने व उनके मार्ग परिवर्तन के लिए झज्जर पुलिस द्वारा झज्जर, बहादुरगढ़ व बादली के एरिया में अलग अलग विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। जो भारी वाहन चालको को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने व उचित मार्ग की तरफ मोड़ने का कार्य करेंगे। भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने व उनके लिए मार्ग परिवर्तन के निर्देश 'दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी' के मद्देनजर किये गये हैं।

दिल्ली की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर भारी वाहनों को रोकने के लिए दिल्ली सीमा व जिला के विभिन्न स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष नाकों पर तैनात झज्जर पुलिस के जवान बाधा रहित आवागमन के लिए भारी वाहनों के चालको की सहायता करेंगें। आमजन की सुविधा एवं यातायात को व्यवस्थित ढ़ंग से चलाये रखने के लिए आवश्यक साजो-सामान से सुसज्जित झज्जर पुलिस के जवानों को दिल्ली सीमा के साथ लगते विशेष नाकों पर तैनात किया गया है। सभी भारी वाहन चालको से आमजन की सुविधा व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये स्थानीय पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।डीएसपी झज्जर (बादली) अरविंद दहिया ने बताया कि भारी कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश को रोकने बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जी 20 मीटिंग के मद्देनजर यातायात तथा कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के संबंध में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े दिशा-निर्देश किए गए हैं। एसपी डॉ अर्पित जैन द्वारा किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

दिल्ली सीमा के साथ लगते नाकों पर तैनात कर्मचारियों को भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने बारे सख्त दिशानिर्देश किए गए हैं। आमजन की सुरक्षा व सुविधा के

## महत्वपूर्ण सूचना

**G20 Summit 2023 के सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर दिनांक 03.09.2023 व 04.09.2023 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित 'ट्रेन्स हैंडलिंग प्लान' संबंधी सार्वजनिक सूचना में आंशिक संशोधन के साथ निम्नलिखित रेलगाड़ियों के निरस्तीकरण की तिथियों में परिवर्तन किया गया है, जो निम्नानुसार है:–**

- रेलगाड़ी सं. 14023 दिल्ली – कुरूक्षेत्र जं. एक्सप्रेस 09.09.2023 एवं 14024 कुरूक्षेत्र जं. – दिल्ली एक्सप्रेस 10.09.2023 को निरस्त की गई थी। अब 14024 को 09.09.2023 एवं 14023 को 10.09.2023 को निरस्त पढ़ा जाए।
- रेलगाड़ी सं. 04283 दिल्ली जं. – रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल 10.09.2023 एवं 11.09.2023 को निरस्त की गई थी। अब 04283 दिल्ली जं. – रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल को 09.09.2023 एवं 10.09.2023 को निरस्त पढ़ा जाए।
- रेलगाड़ी सं. 04286 रेवाड़ी – दिल्ली जं. एक्सप्रेस स्पेशल 10.09.2023 एवं 11.09.2023 को निरस्त की गई थी। अब 04286 दिल्ली जं. – रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल को 09.09.2023 एवं 10.09.2023 को निरस्त पढ़ा जाए।

नोट : अन्य विवरण पूर्ववत रहेगा।

**रेलयात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।**

रेलयात्रियों को परामर्श दिया जाता है कि दिनांक 08, 09 और 10 सितम्बर 2023 को रेलमदद हेल्पलाईन सं. 139 अथवा NTES App पर रेलगाड़ियों की स्थिति देखकर अपनी यात्रा प्लान करें।

रेलमदद वेबसाइट देखें: www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें | आज़ादी का अमृत महोत्सव | G20

उत्तर रेलवे

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

# प्रॉपर्टी टैक्स की OTS स्कीम पर सरकार ने 24 घंटे में ही लगाई रोक

**जालंधर (एजेंसी)**

### डिफाल्टरों को अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार

पंजाब सरकार ने प्रापर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को ब्याज और जुर्माने में छूट के फैसले को रोक लिया है। सोमवार शाम को इस छूट की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन इसके 24 घंटे के भीतर ही इस नोटिफिकेशन को रोक लिया है। स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। यह नोटिफिकेशन गलती से जारी होने की बात कही जा रही है।

हालांकि अफसरों को कहना है कि जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार के नोटिफिकेशन में जो छूट दी गई थी, उससे ज्यादा राहत लोगों को नई नोटिफिकेशन में दी जाएगी। विभाग ने सोमवार के नोटिफिकेशन को रोकने के लिए कई निगमों, कौंसिलों को मंगलवार को ईमेल से संदेश जारी कर दिया है। जालंधर में 80 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर हैं और इन्हें अब नई नोटिफिकेशन इंतजार रहेगा। निगम कमिश्नर ऋषिपाल सिंह ने प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के लिए सितंबर महीने के लिए 10 करोड़ टैक्स कलेक्शन का टारगेट तय किया है।

प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके निर्देश दिया है कि इस साल तय किए गए 45 करोड रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाए। प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक छह महीने के लक्ष्य के तहत 22.50 करोड़ टैक्स का लक्ष्य पूरा किया जाए। अभी तक करीब 12.50 करोड रुपए टैक्स ही इकट्ठा हो पाया है, इसलिए सितंबर महीने में 10 करोड़ रुपये इकट्ठे करने होंगे।

सितंबर में टैक्स कलेक्शन वैसे भी ज्यादा होती है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद टैक्स पर 10 प्रतिशत रिबेट का समय खत्म हो जाता है। इसके बाद 31 दिसंबर तक पूरा टैक्स जमा करवाना पड़ता है और जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। निगम कमिश्नर ने कामर्शियल इमारतों, खास तौर पर बस स्टैंड और इसके आसपास के इलाकों में चल रहे आइलेट्स और इमीग्रेशन सेंटरों की जांच के निर्देश दिए हैं।

# लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने पर वकीलों का हुड्डा के प्लाटों में दोबारा बहाल होगा 10 प्रतिशत कोटा : एडवोकेट मुकेश सैनी

**ओपन सर्च. संवाददाता**

**बहादुरगढ़।** गोहाना के जे के गार्डन में पूरे हरियाणा से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में पहुंचे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने रैली में पहुंचे जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश के अंदर एससी, बीसी और 36 बिरादरी के शोषित वर्गों की आवाज उठने का काम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी कर रहे हैं।

एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि आज बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा कि हमारे हकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है,क्योंकि आज तक सभी पार्टियों ने चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो ,चाहे बीजेपी हो,

इन लोगों ने हमारे लोगों को लुभावने सपने दिखाकर उनकी वोट लेने का काम किया है परंतु हमारे लोगों के हक और अधिकारों को खत्म करने करने का काम किया है। एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने पर हुड्डा के प्लाटो में जो वकीलों का 10 प्रतिशत कोटा था उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मुकेश सैनी ने यह भी कहा की हमारे लोग मानसिक गुलाम है जिनके अंदर एक मानसिक कमी है कि हम जीत नहीं सकते। वही एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि हमें अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा और हमें 2024 की लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम 2024 के चुनाव में 100 फीसदी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बना सकते हैं। हमारे जो लोग दूसरी पार्टियों में उनकी हां हजूरी करके अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं उन लोगों ने इस समाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया है अब लोग जागरुक हो गए हैं। अब समाज एकजुट हो रहा है क्योंकि राजकुमार सैनी की विचारधारा व पार्टी के सभी मुद्दे सर्व समाज के विकास के लिए है।

मुकेश सैनी ने यह भी कहा हम लोगों को दूसरी पार्टियों में छोटा-मोटा लोभ छोड़कर हमें राजकुमार सैनी का साथ देना पड़ेगा, तभी हम सरकार बना सकते हैं। आज हरियाणा का एससी बीसी और 36 बिरादरी का शोषित समाज राजकुमार सैनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए साथ है। एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि हमें एक दूसरे समाज के लोगों का सम्मान करना चाहिए। एडवोकेट मुकेश सैनी ने सभी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने हमारे लोगों की वोट लेकर उन्हें का गला काटने का काम किया है और आज मौजूदा बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, किसान और जवान सड़कों पर है, व्यापारी दुखी है, खिलाड़ियों को न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है।

आज भाजपा सरकार नौकरियां और विकास के मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम में उलझाकर, भारत पाकिस्तान करके और धर्म के नाम पर लोगों को उलझाकर उनके वोट साधने की कोशिश कर रही है। 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने पर गुंडागर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा और बिना भेदभाव के नौकरियां दी जाएगी।

## ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

**CIN: L65929DL1985PLC021037**
**Reg Off: R-815 New Rajinder Nagar New Delhi -110060**
**Corp. Off: 47/18, Basement Rajendra Place Metro Station New Delhi 110060**
**Email Id: alstonetextiles@gmail.com Website: www.alstonetextiles.in,**

**NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the company will be held on Friday 29thSeptember, 2023at 01:00 pm through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of AGM &Annual Report for the Financial Year 2022-23is available and can be downloaded from Company's Website www.alstonetextiles.in&BSE www.bseindia.com

In compliance with section 108 of the Companies Act,2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Members are provided with the facility to cast their votes on a resolution set for in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity share held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 22nd September 2023 ('cut-off date')

The remote e-voting commences on 26thSeptember 2023 at 09:00 am IST and ends on 28thSeptember, 2023 at 5:00 pm. During the period Member may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Member who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

The Member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who acquires share in the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically and hold share as of cut off dates: may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting than he/she can use her/his existing User Id & Password for casting the votes.

If you have not registered your email address with the company/ depository you may please follow below instruction for obtaining login details for e-voting :

| | |
|---|---|
| **Physical Holding** | Please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email toalstonetextiles@gmail.com |
| **Demat Holding** | Please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to alstonetextiles@gmail.com |

Members who have not registered their email addresses with the company may register the same by provide Folio No., Name of shareholder, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email toalstonetextiles@gmail.com&bssdelhi@bigshareonline.com

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting please refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to evoting@nsdl.co.in

The details of AGM are available on the website of the company at www.alstonetextiles.in, BSE at www.bseindia.com

**For Alstone Textiles (India) Limited**
**Shradha Sharma**
**Company Secretary**

**Place : New Delhi**
**Date : 6th September, 2023**

Follow us on : Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in Twitter | @OPENSEARCH2 YouTube | open search E-mail | opensearchenglish@gmail.com

# OPEN SEARCH

National English Daily

PUBLISHED FROM DELHI, GOA & CHHATTISGARH

YEAR : 08 ISSUE : 176 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 07, 2023 Rs. 1/- Pages- 8 RNI No. DELENG/2016/67075

www.opensearch.co.in

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

# Cabinet approves VGF scheme with budgetary support of Rs 3,760 crore

*"The VGF for development of BESS Scheme, with an initial outlay of Rs.9,400 crore, including a budgetary support of Rs.3,760 crore*

VIJAY KUMAR. OPEN SEARCH

***The scheme was announced to harness the potential of renewable energy sources such as solar and wind power and aims to provide clean, reliable, and affordable electricity to the citizens.***

**NEW DELHI :** Union Cabinet on Wednesday approved the Scheme for Viability Gap Funding (VGF) for the development of Battery Energy Storage Systems (BESS) with budgetary support of Rs.3,760 crore. The approved scheme envisages the development of 4,000 MWh of BESS projects by 2030-31, with financial support of up to 40% of the capital cost as budgetary support in the form of Viability Gap Funding (VGF).

The scheme was announced to harness the potential of renewable energy sources such as solar and wind power and aims to provide clean, reliable, and affordable electricity to the citizens.

"The VGF for development of BESS Scheme, with an initial outlay of Rs.9,400 crore, including a budgetary support of Rs.3,760 crore, signifies the government's commitment to sustainable energy solutions," an official statement said.

By offering VGF support, the scheme targets achieving a Levelized Cost of Storage (LCoS) ranging from Rs. 5.50-6.60 per kilowatt-hour (kWh), making stored renewable energy a viable option for managing peak power demand across the country.

The VGF shall be disbursed in five tranches linked with the various stages of implementation of BESS projects. To ensure that the benefits of the scheme reach the consumers, a minimum of 85% of the BESS project capacity will be made available to Distribution Companies (Discoms).

In another decision, the Cabinet has approved an amount of Rs. 1164.53 crore for Industrial Development Scheme (IDS), 2017 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

Under this scheme, the total financial outlay was Rs.131.90 crore. This allocated fund has been exhausted during the financial year 2021-22.

The requirement of an additional fund to meet the committed liabilities up to 2028-2029 is Rs.1164.53 Crore.

"It is anticipated to generate direct employment opportunities for about 48607 people by 774 registered units" it said.

# SC protects 3 senior journalists of EGI from arrest till Sep 11

NEW DELHI, OPEN SEARCH

***The bench of the Apex Court, led by the Chief Justice of India (CJI) Dr Dhananjaya Yeshwant Chandrachud also sought Manipur state's response in the petition filed by the EGI and 3 journalists.***

Supreme Court in its interim order on Wednesday protected three senior Journalists from arrest till September 11, who gave a fact-finding report on behalf of Editors' Guild of India (EGI) on 'biased' reporting by local journalists on the brutal ethnic clash related issues in Manipur.

The bench of the Apex Court, led by the Chief Justice of India (CJI) Dr Dhananjaya Yeshwant Chandrachud also sought Manipur state's response in the petition filed by the EGI and 3 journalists.

While granting interim relief to three journalists, the bench fixed the matter for further hearing to next Monday.

Earlier, at 10.30 am this morning, the Apex Court decided to hear the plea of EGI & 3 Journos over FIRs against them for abetting communal tension in Manipur. The plea was mentioned by senior lawyer, Shyam Divan, appearing for the EGI, and urged the Apex court to hear the matter urgently because the senior journalists involved in the case were apprehending arrest.

Divan said that they are seeking emergent directions under Article 32. The EGI appointed a fact finding committee. The three were senior journalists.

They went to Manipur and made a report and concluded that local news reports were biased. After which, the two FIRs have been registered by the police against the senior journalists. "We are seeking protection from arrest and quashing of FIRs," Divan said.

The matter was mentioned before a bench of CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, and Justice Manoj Misra. The bench asked the petitioners to keep the papers ready on the matter so that it could be heard later during the day.

## BRIEF NEWS

### Sonia Gandhi writes to PM seeking agenda for special session of parliament

NEW DELHI : OPEN SEARCH

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi on Wednesday wrote to Prime Minister Narendra Modi and sought a clear agenda from the government for the upcoming special session of Parliament. In a letter to Modi, Sonia Gandhi alleged that," a special session had been called without any prior discussion with other opposition parties."

"You have convened a special five-day session of the Parliament beginning September 18, 2023. I must point out that this special session has been convened without any consultation with other political parties. None of us have any idea of its agenda," she wrote. The former Congress President added that "all we have been communicated is that all five days have been allocated for government business.' Sonia Gandhi said, "We most certainly want to participate in the Special Session because it will give us an opportunity to raise matters of public concern and importance".

She also mentioned the nine topics in the letter for discussion, including price rise, caste census, and JPC over Adani issues, and expressed hope that "time will be allocated under the appropriate rules for a discussion and debate on these issues". A special session of Parliament has been convened from September 18 to 22. The session will have five sittings. Lok Sabha and Rajya Sabha have notified the dates of the special session.

# CM announces up-gradation of GMS Chandraun in Jaisinghpur AC

SHIMLA : OPEN SEARCH

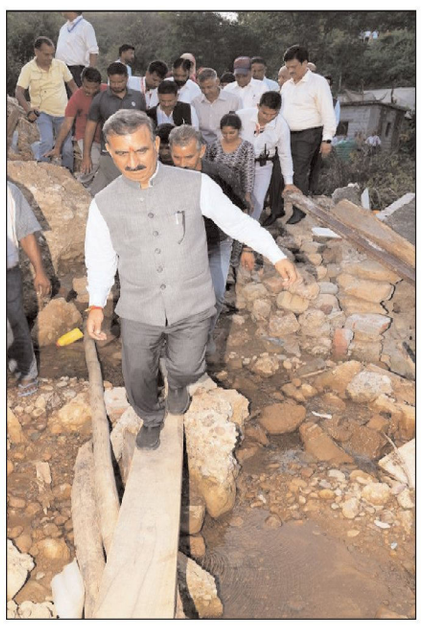

***The Chief Minister said that the government was delivering the special relief package as designed to aid disaster victims.***

Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu during his visit to Jaisinghpur and Sulah assembly segments of Kangra district reviewed the ongoing relief and rehabilitation efforts and interacted with the disaster hit families. He visited various villages in both the constituencies and assessed the damages caused to public and private property. The Chief Minister interacted with the families in severely landslip affected Netru and Dehru Kosari villages of Jaisinghpur and assured of unwavering support to them from the State Government, besides directing the administration to identify suitable land for the families affected by the natural calamity. He also took stock of the Government Middle School in Chandraun and ordered for its renovation and announced to upgrade the school upto 10th class from the next academic session. He also visited landslide hit areas in Siara Kudana. The Chief Minister reiterated to declare ward-wise areas in worst disaster hit Gram Panchayats as disaster-affected areas which would qualify the affected individuals to receive enhanced compensation.

The Chief Minister said that the government was delivering the special relief package as designed to aid disaster victims. Earlier, the amount of compensation given for partial damage to pucca house was Rs. 12,500 and Rs. 10,000 was given for partial damage of kutcha house, which has been enhanced to rupees one lakh now. He assured of all possible assistance to those who suffered losses.

The Chief Minister also inspected the damaged Paprola Bridge and directed the Public Works Department to prepare a DPR for the construction of a new bridge at the same place.

Later, the Chief Minister also visited Bachwain, Parmar Nagar in Sukah and other areas of Sulah assembly and interacted with the disaster hit families. There were reports of land subsidence wherein nine families in Bachwain and 19 in Parmar Nagar were suffered the losses. He directed to allocate of land measuring six marlas each to the affected families. The Chief Minster also met the families having taken shelter in the relief camps and reiterated the state government's resolve of unwavering support to ensure rehabilitation of the affected families.

Chief Minister Parliamentary Secretary, Kishori Lal, Chairman Tourism Development Corporation, Raghubir Singh Bali, MLA Yadvinder Goma, Chairman Himachal Pradesh State Cooperative Rural and Agricultural Development Bank, Sanjay Singh Chauhan, Chairman Kangra Central Cooperative Bank, Kuldeep Pathania, were also present on the occasion.

# Individuals have the right to use either 'India' or 'Bharat': Omar

SRINAGAR : (AGENCY)

Former Chief Minister of Jammu and Kashmir Omar Abdullah on Wednesday said 'Bharat' and 'India' both are part of the constitution and individuals have the right to use either one.

"We are using both the names. If you see the Aeroplane of Prime Minister Narendra Modi in which he is leaving for Indonesia today both India and Bharat are written on the Aeroplane", Omar told media persons on the sidelines of a meeting in south Kashmir's Pulwama. He said if the Prime Minister of India with any reason did not want to use the name India..don't do it. "But at least the name should not be removed from the constitution without our consent," he said. "If you remove the name India from where you are going to remove it ...do the name of State Bank of India would be changed, ISRO which recently did successful mission of Chandrayaan to the moon is going to be changed...IIT, IIM ...so many institutions are there on the name of India and how many they will change", he questioned.

He said if they (government) are concerned about the opposition parties having put their name INDIA..then we will change our name.."we don't want to put the nation in trouble. We have not come here to increase the expenditure of the nation, rather to decrease it", Omar asserted. The National Conference Vice President said "if we will get a little hint that it is being done because the opposition alliance have chosen the name INDIA, we will change our name..there is no need to change the name of the nation.

# IT sector's future lies in the hands of dedicated educators : Khaunte

PANAJI : OPEN SEARCH

***The objective of the event was to recognise the educators, teachers, trainers and Ed-Tech startups dedicated towards educating and empowering students in information technology.***

The department of information technology, electronics and communications, Goa felicitated IT educators at the hands of Rohan Khaunte, Minister of Information Technology, Electronics and Communications. The objective of the event was to recognise the educators, teachers, trainers and Ed-Tech startups dedicated towards educating and empowering students in information technology. Among those felicitated were professors from engineering institutions: Dr. Nilesh Fal Desai, Goa College of Engineering; Dr. Gaurang Patkar, Don Bosco College of Engineering, Fatorda; Manjusha Sanke, Shree Rayeshwar Institute of Engineering & Information Technology, Shiroda; Snehal Bhogan, Agnel Institute of Technology and Design, Assagao; Tech-For-Goa Fellows – Sasmeet Nadkarni, Siddhi Parodkar; computer teachers from government/aided schools in the state- Samita Naik, St. Elizabeth's High School, Bardez; Canyton Crasto, St. Thereza's Convent High School, Raia, and other teachers. Additionally, the startup from Goa in the Ed-Tech sector- Suvarna Surlekar – Funminds Learning Pvt. Ltd. and Damodar Patkar – Bodhami Pvt. Ltd. The other dignitaries present on the occasion were Suneel Anchipaka, IAS, director of information technology, electronics and communications; Agnelo Fernandes, commissioner, labour and employment, Goa; D. S. Prashant, CEO.

# 'Vidya Samiksha Kendra' to be set up to monitor schools

PANAJI : OPEN SEARCH

*In view of the heavy devastation at other places including Utpur and Kakkar, the Chief Minister directed the district administration to declare them as disaster-affected areas.*

Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday announced that a monitoring control room called 'Vidya Samiksha Kendra' will be set up to monitor schools, students, and teachers as also to gather valuable data every month, so as to transform the education sector of the state. The announcement was made during the 62nd Teachers' Day function held in the Darbar Hall of Raj Bhavan.

The 'Vidya Samiksha Kendra' will enable real-time monitoring of schools, students, and teachers. It will also gather valuable data every month to improve governance and provide vital support for enhancing student learning.

"The nationwide mechanism, which will be set up soon in our state, aims to monitor the performance of teachers and students. It will be set up in Panaji," the Chief Minister said.

Addressing concerns about unemployment, Sawant maintained that there are ample job opportunities in Goa for those willing to work. He underscored the government's commitment to nurture skilling to ensure that no youth faces unemployment.

He urged the youth, who have completed their education or chosen not to pursue further studies, to join one-year apprenticeship programme in government or private sectors.

Sawant said the government has not only invested in construction of buildings but also introduced subjects like coding and robotics in government and aided schools, preparing students for the digital age. The Chief Minister highlighted the pivotal role teachers play, especially in rural areas where parents are less informative of career options. He emphasised on the significance of teachers in guiding students in the 10th and 12th Standards, helping them make informed decisions about their careers. Sawant pointed to the improvements made in the education sector without substantial investments. He highlighted the Prime Minister Kaushal Vikas Yojna (PMKVY) as a means to open up various skill development opportunities, offering alternatives through ITI courses for those who may not have excelled academically.

The Chief Minister said the state is actively implementing the new national education policy in higher education.

# UK to ban Russia's Wagner mercenary group as terrorist organisation

***Certain offences related to banned terror organisations can result in 14 years imprisonment in the country***

**LONDON : (AGENCY)**

The UK government will table a draft proscription order in the House of Commons on Wednesday which will impose a ban on Russia's mercenary Wagner Group as a terrorist organisation. The proscription order will make it illegal to be a member of or support the Russian group in the UK, the Home Office said.

Certain offences related to banned terror organisations can result in 14 years imprisonment in the country. As part of the Home Office draft order, Wagner's assets can also be categorised as terrorist property and seized.

"Wagner is a violent and destructive organisation which has acted as a military tool of [President] Vladimir Putin's Russia overseas," said UK Home Secretary Suella Braverman. "While Putin's regime decides what to do with the monster it created, Wagner's continuing destabilising activities only continue to serve the Kremlin's political goals. They are terrorists, plain and simple – and this proscription order makes that clear in UK law," she said.

The Indian-origin Home Secretary claimed that Wagner has been involved in "looting, torture and barbarous murders". "Its operations in Ukraine, the Middle East and Africa are a threat to global security. That is why we are proscribing this terrorist organisation and continuing to aid Ukraine wherever we can in its fight against Russia," she added.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has previously called for the Wagner Group to be treated as a terrorist organisation. The mercenary group, which was led by Yevgeny Prigozhin until he was killed in a plane crash last month, has played a prominent role in the Russian conflict with Ukraine. It is also known to be active in conflicts in other war-torn regions of Syria and Africa. The crash that killed Prigozhin occurred just months after he mounted an attempted coup against Russia's military leadership, ultimately calling into question Putin's authority as Russian President.

There have been conspiracy theories floating around the suspect explosion that caused the Wagner leader and his inner circle's death in the crash.

The UK Home Office said it considered the nature and scale of the organisation's activities as well as the threat they pose to British nationals abroad in deciding on the proscription order. It will bring the group in line with other banned terrorist organisations such as the Islamic State (ISIS) and Al Qaeda.

# North Korea's leader Kim Jong-un plans rare foray into Russia

**WASHINGTON : (AGENCY)**

Kim Jong-un, the leader of North Korea, plans to travel to Russia this month to meet President Vladimir Putin to discuss the possibility of supplying Russia with more weaponry for its war in Ukraine and other military cooperation, according to American and allied officials. In a rare foray from his country, Kim would travel from Pyongyang, North Korea's capital, probably by armoured train, to Vladivostok, on the Pacific Coast of Russia, where he would meet with Putin, the officials said. Kim could possibly go to Moscow, though that is not certain.

Putin wants Kim to agree to send Russia artillery shells and anti-tank missiles, and Kim would like Russia to provide North Korea with advanced technology for satellites and nuclear-powered submarines, the officials said. Kim is also seeking food aid for his impoverished nation. Both leaders would be on the campus of Far Eastern Federal University in Vladivostok to attend the Eastern Economic Forum, which is scheduled to run from Sunday to September 13, according to the officials. Kim also plans to visit Pier 33, where naval ships from Russia's Pacific fleet dock, they said. North Korea celebrates the anniversary of its founding on Saturday. On Wednesday, the White House warned that Putin and Kim had exchanged letters discussing a possible arms deal, citing declassified intelligence. A White House spokesperson, John F. Kirby, said high-level talks on military cooperation between the two nations were "actively advancing." US officials declined to give more details on the state of personal ties between the leaders, who are considered adversaries of the United States. The new information about a planned meeting between them goes far beyond the previous warning. The intelligence relating to the plans has not been declassified or downgraded by the US, and the officials describing it were not authorised to discuss it. They declined to provide details on how spy agencies had collected the information. While the White House declined to discuss the new intelligence, Adrienne Watson, a National Security Council spokesperson.

# Will only agree India trade deal approach that works for UK, says Prime Minister Rishi Sunak

**LONDON : (AGENCY)**

The free trade agreement (FTA) talks with India are "progressing" and Britain will only agree to a pact that works for the whole of the United Kingdom, Prime Minister Rishi Sunak told his ministers. Ahead of his first visit to India as UK Prime Minister to attend the G20 World Leaders' Summit in New Delhi later this week, Sunak updated his top team on the ongoing trade talks, which have completed 12 rounds of negotiations, during a Cabinet meeting on Tuesday.

The British Indian leader described India as an "indispensable partner" of the UK across all spheres of bilateral cooperation, which he is keen to strengthen further. "He said negotiations around a free trade deal were progressing and that he would only agree to an approach which worked for the whole of the UK," notes a Downing Street readout of the Cabinet meeting.

"The Prime Minister said India was an indispensable partner of the UK, both economically and in addressing the global challenges all democracies are facing. He said we must now strengthen the UK-India relationship," it said.

UK Business and Trade Secretary Kemi Badenoch, who has returned from a visit to India after talks with Commerce and Industry Minister Piyush Goyal last month, also updated the UK Cabinet on the FTA negotiations, saying that "India is already one of the UK's largest trading partners, with a relationship worth GBP 36 billion a year". "The Prime Minister concluded Cabinet by setting out his desire to use our growing relationship in trade, defence, and technology to build a lasting and deep partnership with India which benefits the people of the UK for decades to come," Downing Street said.

The 43-year-old leader is expected to receive a grand welcome when he arrives in New Delhi, with bilateral talks expected with Prime Minister Narendra Modi during the course of his stay. While the details of the visit are yet to be confirmed by Downing Street, some UK media reports have indicated.

# Joe Biden at G20 Summit to focus on progress on climate, reshaping multilateral development banks: White House

**US : (AGENCY)**

The key focus areas for President Joe Biden at the G20 Summit include delivering for developing nations, making progress on key issues like climate, technology and reshaping the multilateral development banks, the White House has said, expressing hope that the bloc will be able to make headway on those topics under Prime Minister Narendra Modi's leadership. On Thursday, President Biden will travel to New Delhi to attend the G20 Leaders' Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi and on Saturday and Sunday, the President will participate in the official sessions of the G20 Summit. As Biden heads to the G20, he is committed to working with emerging market partners to deliver big things together, National Security Advisor Jake Sullivan said during a press briefing on Tuesday. "That's what we believe the world will see in New Delhi this weekend," he said.

America's commitment to the G20 has not wavered, and it hopes the G20 Summit in New Delhi will show that the world's major economies can work together even in challenging times, Sullivan said. "So, as we head into New Delhi, our focus is going to be on delivering for developing countries; making progress on key priorities for the American people, from climate to technology; and showing our commitment to the G20 as a forum that can actually, as I said before, deliver," he said.

"And thanks to the leadership of Prime Minister Modi and India's presidency, we hope we'll be able to do all of those things," Sullivan said. On what the US is bringing to the table at the summit, Sullivan said one of America's main focuses heading into the G20 is delivering on an agenda of fundamentally reshaping and scaling up the multilateral development banks, especially the World Bank and the IMF. "We know that these institutions are some of the most effective tools that we have for mobilising transparent, high-quality investment into developing countries. And that's why the United States has championed the major effort that is currently underway to evolve these institutions so that they are up to the challenges of today and tomorrow," he said.

Just last month, President Biden asked Congress for additional funds that would have the impact of increasing World Bank financing by more than USD 25 billion. "And we're working to make sure other partners follow our lead," he said.

"And at the G20, we have been leading an effort that we hope will see the G20 endorse this level of ambition and deliver a broader vision of multilateral development banks that are better, bigger, and more effective," he said. President Biden will also be calling on G20 members as leaders in the global economy to provide meaningful debt relief so that low- and middle-income countries can regain their footing after years of extreme stress, Sullivan said. "He'll be clear that the United States expects real progress on ongoing cases by the World Bank and IMF Annual Meetings in Marrakech (Morocco) next month. And he will be clear that we need all G20 members to be constructive and at the table with no exceptions," he said. The bloc also be making progress on other key priorities from climate, to health, to digital technology, including commitments to a more inclusive digital transformation and a responsible path and approach.

# Ukraine rebuffs Turkish suggestion that Kyiv should soften stance on grain deal

**KYIV : (AGENCY)**

A senior Ukrainian official on Tuesday rebuffed a suggestion by Turkey that Kyiv should soften its stance to revive the Black Sea grain deal, saying Ukraine would not support sanctions relief for Moscow or a policy of "appeasement". "Let's be realistic after all and stop discussing non-existent options, much less encouraging Russia to commit further crimes," presidential adviser Mykhailo Podolyak told Reuters. He made the remarks when asked about comments made by Turkish President Tayyip Erdogan on Monday after talks with Russian leader Vladimir Putin. Podolyak said that Russia was "extremely interested" in the destruction of Ukrainian seaports and grain transhipment infrastructure. He said Russia did not need a grain deal and that Moscow was interested in cutting Ukraine off from the global grain market, pushing up grain prices. "Where is the field for Ukrainian "softening" here?" Podolyak said. "And let us be clear, we will definitely not play the 'policy of appeasement of the aggressor'... and indulgence in the programme.

# *Blocking evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists without justification smacks of doublespeak: India*

**UNITED NATIONS : (AGENCY)**

India has told the UN Security Council that blocking evidence-based proposals for blacklisting globally sanctioned terrorists without giving justifications is uncalled for and "smacks of doublespeak", a thinly-veiled reference to China and Pakistan. "The working methods of the UNSC Sanctions Committees continue to dent the credibility of the UN Security Council," India's Permanent Representative to the UN Ambassador Ruchira Kamboj said here on Tuesday.

Speaking in the Security Council's open debate on Working Methods, Kamboj said "genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to Council's commitment in tackling the challenge of terrorism." She stressed that the working methods of Sanctions Committees must emphasise transparency, and objectivity in listing and delisting and should not be based on political considerations. Kamboj's remarks were a veiled reference to China and its all-weather friend Pakistan. Beijing has repeatedly placed holds and blocks on bids by India and its allies to list Pakistan-based terrorists. The latest example came in June this year when China blocked a proposal by India and the US under the 1267 Al Qaeda Sanctions Committee of the UN Security Council to designate Lashkar-e-Taiba terrorist Sajid Mir, wanted for his involvement in the 26/11 Mumbai terrorist attacks, as a global terrorist.

Kamboj highlighted that India, an eight-term elected member of the UNSC, has some key concerns about the need to improve the working methods of the Security Council.

"What we... need is a Security Council that better reflects the geographical and developmental diversity of the United Nations today. A Security Council where voices of developing countries and unrepresented regions, including Africa, Latin America and the vast majority of Asia and Pacific, find their due place at this horseshoe table," she said.

India, the world's most populous nation, underscored that an expansion of the Council in both categories of membership is absolutely essential.

"This is the only way to bring the Council's composition and decision-making dynamics in line with contemporary geo-political realities," Kamboj said. She added that the international community can no longer hide behind the smokescreen of the Inter-Governmental Negotiations (IGN) in the General Assembly and continue to pay lip service by continuing to deliver statements in a process that has no time frame, no text and no defined goal to achieve. "If countries are truly interested in making the Council more accountable and more credible, we call on them to come out openly and support a clear pathway to achieve this reform in a time-bound manner, through the only established process in the UN, which is by engaging in negotiations based on text and not through speaking at each other, or past each other, as we have done for the last three decades," she said. Kamboj underlined that as the threats to international peace and security evolve, so must this Council. "We ask those blocking progress on this vital issue to heed the calls for genuine reform, and contribute to making this Council truly fit for purpose for the 21st century." She noted that merely fixing the working methods of the Security Council will never be good enough to rectify its fundamental flaw, its lack of representative character. "To continue to deny member states of the Global South a voice and role in Council's decision-making only lowers the Council's credibility," she said.

Another area of concern highlighted by India was that the selection of chairs of subsidiary bodies and distribution of penholderships must be made through a process that is open, transparent, based on exhaustive consultations, and with a more integrated perspective. "The consensus of E-10 on chairs of subsidiary bodies to be assumed by the E-10 themselves must be honoured by the P5.

**NORTHERN RAILWAY**

**OFFICE OF THE MEDICAL DIRECTOR, NORTHERN RAILWAY CENTRAL HOSPITAL, BASANT LANE, NEW DELHI-110055**

File No: E/Med/SR/74/CH/2023 Advt.No. NRCH/SR/2023/03

**ENGAGEMENT OF SENIOR RESIDENTS**

Applications are invited from eligible candidates for engagement to the post of Senior Resident under Senior Residency Scheme at Northern Railway Central Hospital, New Delhi. Detailed advertisement with VACANCY STATUS, Terms & Conditions, Format of Application form is available on Northern Railway website www.nr.indianrailways.gov.in under head News & Recruitment Info)

MEDICAL DIRECTOR, NORTHERN RAILWAY CENTRAL HOSPITAL, BASANT LANE, NEW DELHI-110055 2775/2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

**ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED**

**CIN: L65929DL1985PLC021037**
**Reg Off: R-815 New Rajinder Nagar New Delhi -110060**
**Corp. Off: 47/18, Basement Rajendra Place Metro Station New Delhi 110060**
**Email Id: alstonetextiles@gmail.com Website: www.alstonetextiles.in,**

**NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the company will be held on Friday 29thSeptember, 2023at 01:00 pm through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of AGM &Annual Report for the Financial Year 2022-23is available and can be downloaded from Company's Website www.alstonetextiles.in&BSE www.bseindia.com

In compliance with section 108 of the Companies Act,2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Members are provided with the facility to cast their votes on a resolution set for in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity share held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 22nd September 2023 ('cut-off date')

The remote e-voting commences on 26thSeptember 2023 at 09:00 am IST and ends on 28thSeptember, 2023 at 5:00 pm. During the period Member may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Member who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

The Member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who acquires share in the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically and hold share as of cut off dates: may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting than he/she can use her/his existing User Id & Password for casting the votes.

If you have not registered your email address with the company/ depository you may please follow below instruction for obtaining login details for e-voting :

| | |
|---|---|
| **Physical Holding** | Please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email toalstonetextiles@gmail.com |
| **Demat Holding** | Please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to alstonetextiles@gmail.com |

Members who have not registered their email addresses with the company may register the same by provide Folio No., Name of shareholder, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email toalstonetextiles@gmail.com&bssdelhi@bigshareonline.com

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting please refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to evoting@nsdl.co.in

The details of AGM are available on the website of the company at www.alstonetextiles.in, BSE at www.bseindia.com

**For Alstone Textiles (India) Limited**
**Shradha Sharma**
**Company Secretary**

**Place : New Delhi**
**Date : 6th September, 2023**